किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो ऐसी इकाइयों/उद्योगों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) उद्योग लगाने के लिए भूमि के अधिग्रहण और जिन जिन लोगों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के कारण बेदखल कर दिया जाता है, उनके पुनर्वास तथा उनके रोजगार आदि की व्यवस्था करने का मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । भारत सरकार कोई आंकडे नहीं रखती ।

Sick Public Sector Enterprises

4735. DR. BAPU KALDATE:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some more public sector units have been added to the sick public sector undertakings list during 1990-91;

(b) if so, what are the details thereof stating the total number of sick units as on date; and

(c) the estimated number of workers affected with the adding up of the new sick units in the list of already identified public sector sick units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) As per the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA) the sick industrial units are referable to the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for formulation of revival/rehabilitation plans. For the non-industrial sick units, the respective Managements and the administrative Ministries/Departments are required to formulate similar revival schemes. Details of these enterprises are given below:—

	1989-90	1990-91
1. (a) Sick Public Enterprises referable to BIER under provision of SICA	50	54
(b) Sick Public enterprises not referable to BIFR	8	13
2. Total number of sick Units	58	67
3. Estimated number of workers involved (Reguiar employees)	4·08 (No. in lakhs)	3·97

कार का निर्माण करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को पेशकश

4736. **श्री शांति त्यागी :**
श्री विनोद शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सस्ती तथा छोटी डीजल कार निर्माण करने के लिए एक फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी को पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित कार की कीमत मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति की पहुंच के भीतर होगी ।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।